



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुकवार, 17 सितम्बर, 2004/26 भाद्रपद, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

(रजिस्ट्रेशन-स्टाम्प)

अधिसूचना

शिमला-2, 31 अगस्त, 2004

संख्या 5-10/74-राजस्व-ए.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यथासांग भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5-10/74-रैव-ए, तारीख 18 मार्च, 2002 की निरन्तरता में, हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों तथा स्थायित्व निधियों के कर्मचारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1968 के अधीन कोऑपरेटिव बैंकों राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपने निवास गृह के निर्माण या क्रय के लिए गृह निर्माण अग्रिम को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे बैंकों के पक्ष में निष्पादित आदमान पत्रों की निम्नलिखित अर्थात् बिना सन्धा बन्धक पर प्रभार्य, पूर्ण स्टाम्प शुल्क की समस्त हिमाचल प्रदेश में, दूरन्त प्रभाव से छूट देते हैं:

परन्तु रटाय गल्ल में वी गई ऐसी छूट, प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपने जीवन में केवल एक गल्ल निर्माण के लिए, बल लागू करण की अधिकतम सीमा के अन्दर ही होगी।

आदेश द्वारा,
सी० पी० पाण्डे,
वित्तीय तथा सचिव।

[Authoritative English text of the notification No. 5-10/74-Revenue-A, dated 31-8-2004 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

**REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)**

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 31st August, 2004

No. 5-10 74 Revenue-A. In supersession of this Department Notification No. 5-10/74-Revenue-A, dated 18-3-2002, and in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899), as applicable to State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to remit the entire stamp duty chargeable on instruments of Hypothecation *i. e.* mortgage without possession executed by the employees of H. P. State Government, the employees of the H. P. State Govt. Public Sector Undertakings and the employees of autonomous bodies for securing a house building loan from the Co-operative Banks registered under the H. P. Co-operative Societies Act, 1968, Nationalised Banks and Himachal Pradesh Regional Rural Banks, for construction or purchase of a dwelling house for their own use and executed in favour of aforesaid banks, with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh :

Provided that the stamp duty so remitted shall be for one H. B. A. per employee in his career further subject to the maximum ceiling of Rs. 10.00 lakhs.

By order,

C. P. PANDEY,
F.C.-cum-Secretary.